5 APR 2017

दै. नव दुनियाँ, भोपाल

अच्छी खबर | पहली बार की गिनती से बाघों को कम आंकना गलत

टाइगर स्टेट बना रहेगा मध्यप्रदेश

रामकुमार भारती भोपाल

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण सचिव डा.टी चटर्जी ने भरोसा दिलाया है कि मध्यप्रदेश को मिला टाइगर स्टेट का खिताब फिलहाल कायम रहेगा। एक बार की गिनती में हम यह आकलन नहीं कर सकते कि प्रदेश में बाघों की संख्या कम हुई है। लिहाजा अब भी यह राज्य टाइगर स्टेट है और आगे भी रहेगा, क्योंकि दोबारा गणना होने पर बाघों की संख्या बढ़ सकती है।

सोमवार को आईआईएफएम में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए डा. चटर्जी ने नवदुनिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे देश में बाघों की संख्या 1706 है। तमिलनाडु में 350 और कर्नाटक में 300 बाघ होने के प्रमाण मिले हैं।

■ बाघों की संख्या बढ़ने की गति धीमी

लेकिन मध्यप्रदेश में 257 बाघों की संख्या के आधार पर यह तो माना ही जा सकता है कि प्रदेश में बाघों की संख्या जितनी बढ़नी चाहिए, उतनी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि दोबारा गणना होने पर बाघों की संख्या में वृद्धि हो जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताया गया कि कुछ क्षेत्रों को गणना में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते बाघों की संख्या में कमी का भान हो रहा है। चटर्जी ने कहा कि केंद्र से जल्द ही एक टीम मप्र आएगी और बचे हुए क्षेत्रों में गणना करेगी।

ग्रीन इंडिया मिशन में ऊर्जा वन

डा. चटर्जी के मुताबिक केंद्र ने वनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह तय किया है कि ग्रीन इंडिया मिशन में ऊर्जा वन और चारागाह विकास को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सभी राज्यों के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत 'पहले आओ और पहले पाओ' के आधार पर राशि का आवंटन होगा। - शेष पेज 9 पर

टाइगर स्टेट...

आईआईएफएम सेंटर बनेगा : डा. चटर्जी के मुताबिक ग्रीन इंडिया मिशन के तहत आईआईएफ को एक सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। महकमे की ओर से वनकर्मियों के लिए चलने वाले शिक्षा कार्यक्रम और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की दिशा में और काम किया जाएगा। वैसे प्रदेश में विभागीय आंकड़ों के सुरक्षित संधारण के लिए वन महकमे की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा ने भोपाल मुख्यालय में राज्यस्तरीय डाटा सेंटर स्थापित किया है।

दस दिन में भेजेंगे प्रस्ताव: पीसीसीएफ आरके दवे के मुताबिक ग्रीन इंडिया मिशन के तहत उर्जा वन और चारागाह विकास के लिए केंद्र से राशि लेने के लिए दस से पंद्रह दिन के अंदर प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इसमें पश्चिमी मध्यप्रदेश व बुंदेलखंड के करीब एक दर्जन से अधिक जिलों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश से जल्द प्रस्ताव भेजे जाने पर 20 से 30 करोड़ मिल सकते हैं।